

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी- महावीरसिंह जोधा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

03/2019

28.01.2018

12.04.2019

1 भंवरसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई

प्रार्थी

वनाम

1. उम्मेदसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
2. अचलसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
3. भैरूसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
4. जेटूसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
5. अर्जूनसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
6. पर्वतसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
7. दानसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
8. लहरकंवर पत्नी जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
9. भवरसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
10. चनणसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
11. तगतसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
12. केसरकंवर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
13. गीताकंवर पत्नी हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी आसरलाई
14. अचलसिंह पुत्र हुकमसिंह आयु 13 वर्ष नाबालिग
15. विक्रमसिंह पुत्र हुकमसिंह आयु 11 वर्ष नाबालिग
16. आसुकंवर पुत्री नारायणसिंह
17. सिरुकंवर पुत्री नारायणसिंह
18. लीलाकंवर पुत्री नारायणसिंह
19. भवरसिंह पुत्र पेपसिंह
20. भूरसिंह पुत्र पेपसिंह
21. चैनसिंह पुत्र पेपसिंह
22. तुलछसिंह पुत्र पेपसिंह
23. देवकंवर पत्नी पेपसिंह
24. हनंवतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
25. गेनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह सभी कौम राजपूत निवासी ग्राम आसरलाई
26. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर

अप्रार्थीगण

साहायक जिलाधीश शेरगढ
जिला जोधपुर

स्थिति-

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जेटूसिंह खीची
प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिंह भाटी

आदेश

प्रकरण में पेश किये गये प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्राणी द्वारा 251 (अ) का प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा बाधित होने से प्रार्थना पत्र ही मेन्टनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 229 रकबा 01 बीघा 9 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी है ऐसी स्थिति में आबादी की भूमि में से कोई रास्ते का प्रावधान धारा 251(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है केवल खेत में से एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है जबकी अप्रार्थीगण की आबादी भूमि जहाँ पर उसकी ढाणिया पक्के मकान आए हुए है। उसमें से कोई रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है तथा उक्त प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकार में नहीं होने से उसका क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र गैर मुमकीन आबादी भूमि के संबंध में सुनने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 में बने प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र ही मेन्टनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है। खसरा नम्बर 240 के सभी खातेदारों द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है मात्र एक खातेदार को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है खसरा नम्बर 240 का रकबा 244.14 बीघा है जिसकी नक्शे में एंव राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम की हुई नहीं है। खसरा नम्बर 240 में बिना तरमीम किए यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि प्राणी की ढाणी कहाँ पर आई हुई है इस कारण उक्त अपूर्ण प्रार्थना पत्र सभी सह खातेदारान को पक्षकार बनाए बिना पेश किया गया है जो खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्राणी का प्रार्थना पत्र मय भारी हर्जे व खर्चे सहित खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावे।

धारा 251(ए) का प्रार्थना पत्र खातेदारी में दर्ज भूमि के रास्ते बाबत प्रस्तुत किया गया जो किसी प्रकार से विधि द्वारा बाधित नहीं है। जिस आराजी में दावा प्रस्तुत किया गया है या रिकॉर्ड में गै.मू.आबादी भूमि दर्ज होकर अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है जाहिरा तौर पर इस प्रकार की आराजी गावाई आबादी नहीं है क्योंकि धारा 92 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आराजी को आबादी घोषित नहीं किया गया है और जो आराजी गावाई आबादी घोषित नहीं हो गई हो तथा राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार के खाते में दर्ज हो उस आराजी के संबंध में दावे को सुनने का राजस्व न्यायालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। खसरा नम्बर 240 व सभी खातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है क्योंकि रास्ता प्राणी का ही बाधित हो रहा है इसलिए प्राणी ने रास्ते हेतु उक्त आवेदन प्रस्तुत

किया है जो विधि अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया गया है अप्रार्थीगण मामले को लम्बा करने की नियत से गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। जवाब पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी कॉस्ट के आधार पर खारिज फरमावे।

प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

मैने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखे कथनों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया, प्रार्थी अधिवक्ता ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में लिखे कथनों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया।

मैने दोनों अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आबादी की भूमि में से कोई रास्ते का प्रावधान धारा 251(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है केवल एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने का प्रावधान है। आबादी भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है उक्त प्रार्थना पत्र गैर मुमकीन आबादी भूमि के संबंध में होने से प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 में बने प्रावधानों के अनुसार 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक जिलाधीश
एवं उपखण्ड अधिकारी शीरगढ